



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, 22 जनवरी, 2004/2 माघ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जनवरी, 2004

संख्या एल० एल० आर०-डी (6)-32/2003-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-01-2004 को यथा अनुमोदित हिमाचल

प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक 20) को वर्ष 2004 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2004 का अधिनियम संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2004 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- (2) यह 30 मई, 1994 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, "तथा उसके ऐसे अनुलग्नकों या फर्नीचर की दशा में जो उसके साथ उपयोग या उपभोग के लिए" शब्दों के स्थान पर "की दशा में सकल वार्षिक किराया, जिस पर कि ऐसा गृह या निर्माण, इसके अनुलग्नकों और किसी प्रकार के फर्नीचर सहित जो उसके साथ उपयोग या उपभोग के लिए किराए पर दिया जा सकेगा," शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 2 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रकाशन पर या इससे पूर्व किसी भी समय मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अवधारित किया गया किसी गृह या निर्माण (बिल्डिंग) का वार्षिक मूल्य, किया गया कोई निर्धारण या की गई कर की वसूली या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिमान्यतः और विधिपूर्वक अवधारित, निर्धारित, वसूल की गई, की गई और सदैव की गई समझी जाएगी। विधिमान्य-करण।
4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्-द्वारा निरसन किया जाता है। 2003 के अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियां।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (THIRD AMENDMENT)
ACT, 2003

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST JANUARY, 2004)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title
and comm-
encement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Act, 2003.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 30th day of May, 1994.

Amendment
of section
2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), in clause (b), for the words "together with its appurtenances or any furniture that may be let for use and", the words and sign "the gross annual rent at which such house or building together with its appurtenances and any furniture that may be let for use or" shall be substituted.

Validation.

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in the principal Act, any annual value of house or building determined, any assessment or recovery of tax made or any action taken or anything done under the provisions of the principal Act, at any time on or before the publication of the Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Act, 2003 shall and shall always be deemed to have been validly and lawfully determined, assessed, recovered, taken or done under the provisions of the principal Act as amended by this Act.

Repeal of
Ordinance
No. 6 of
2003 and
savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.